



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर में केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित चिंतन शिविर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग राज्यमंत्री डॉ मंजू बाघमार, ओडिशा की उपमुख्यमंत्री पार्वती परिदा तथा केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

‘मोदी सरकार में 100 रुपये भेजते हैं तो सौ रूपए ही मिलते हैं’

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा, कई पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपया भेजते हैं, पर, 15 पैसे ही पहुँचते हैं

उदयपुर, 11 जनवरी (कांस)। मुख्यमंत्री ने शनिवार को उदयपुर में केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित चिंतन शिविर के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह चिंतन शिविर महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। शिविर में हम साथ मिलकर इनके भविष्य को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में चिंतन करें, जिससे महिला एवं बाल विकास को नई दिशा मिले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जब तक हम किसी बात का मूल्यांकन नहीं करेंगे, तब तक हमें जमीनी स्तर का परिणाम नहीं पता चलेगा। हमें हमारी योजनाओं का आकलन करना होगा, आकलन ठीक होगा तो योजनाएं और अच्छी होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे कई पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। अब मोदी सरकार के आने के बाद 100 रुपए भेजते हैं तो नीचे पूरे के पूरे 100 रुपए मिलते हैं।

शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृशक्ति तथा बच्चों के समग्र विकास के लिए समर्पित हैं। उनके अनुसार, देश

- केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा केन्द्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, ओडिशा की उपमुख्यमंत्री पार्वती परिदा, राजस्थान की राज्य मंत्री मंजू बाघमार तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, शिक्षा, सामाजिक सम्मान आदि के प्रति राज्य सरकार पूरी तरह संवेदनशील है।

में महिलाएं, युवा, किसान तथा मजदूर, चार जातियां हैं, जिनके उत्थान एवं सर्वांगीण विकास के लिए सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को राज्य सरकार ने 5 हजार से बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपये कर दिया है। साथ ही, दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 10 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पालनहार योजना से राज्य के 6 लाख बच्चों के लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जा रही है।

आयोजित यह चिंतन शिविर महिला बाल विकास के समेकित उत्थान का नया अध्याय लिखेगा। केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि चिंतन शिविर का मंच विचारों को कार्यों और कार्यों को परिणाम में बदलने का अवसर सिद्ध होगा।

उपमुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार विकसित भारत विकसित राजस्थान के लक्ष्य को लेकर निरंतर आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार महिला सम्मान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लगातार काम कर रही है।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री शर्मा ने दीप प्रज्वलित करते हुए शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग राज्यमंत्री डॉ मंजू बाघमार, ओडिशा की उपमुख्यमंत्री पार्वती परिदा, महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव महेंद्र सोनी, निदेशक ओपी बुनकर, अतिरिक्त निदेशक मेघराजसिंह मौणा सहित केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी सहित आदि मौजूद थे।

सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु राज्यपाल को हटाने की याचिका

तमिलनाडु, 11 जनवरी। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्यपाल अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से पूरा नहीं कर रहे हैं। आरोप है कि उनका कार्य राज्य की संवैधानिक प्रणाली के खिलाफ जा रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्यपाल के कामकाज के तरीके से राज्य सरकार और शासन के बीच असहमति और तनाव पैदा हो रहा है। याचिका में राज्यपाल के कुछ फैसलों और उनके काम करने का ढंग पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि राज्यपाल ने राज्य सरकार के साथ कई मुद्दों पर बिना विचार किए हुए हस्तक्षेप किया है, जिससे राज्य की राजनीति में अनावश्यक विवाद बढ़े हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्यपाल को अपनी संवैधानिक भूमिका

- याचिका में आरोप है कि राज्यपाल आर.एन. रवि का कार्य राज्य की संवैधानिक प्रणाली के खिलाफ है।

निभाने के लिए और अधिक संतुलित और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तमिलनाडु में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच पहले भी कई बार मतभेद सामने आ चुके हैं। इन मतभेदों के कारण राज्य की राजनीति में खलबली मची रहती है। राज्य सरकार और विपक्ष दोनों ही राज्यपाल के फैसलों को लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं। ऐसे में यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करना, राज्यपाल के खिलाफ असंतोष का एक और बड़ा कदम माना जा रहा है।

तथाकथित सी.ए.जी. रिपोर्ट...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) ऑफ थिनिस्टर्स (जी.ओ.एम.) ने विशेषज्ञ समिति को सिफारिशों की अनदेखी कर दी। भाजपा ने, आप सरकार पर भारी झूठाचार तथा कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुये, रिपोर्ट के कथित निष्कर्षों का तुरन्त फायदा उठाने का प्रयास किया। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा, “आगर उनकी (आप) नीतियां इतनी ही अच्छी थीं, तो वे घबराये हुये क्यों हैं? आज आप के पास दिल्ली की टूटी सड़कों, घरों में गंदे पानी की सफाई, बढ़ते हुये बिजली के बिलों, कूड़े-करकट के ढेरों तथा प्रदूषण का कोई जवाब नहीं है। आज दिल्ली की जनता “आप-दा” से छुटकारा पाना चाहती है।”

आप नेता सांसद संजय सिंह ने कहा, “कहाँ है सी.ए.जी. रिपोर्ट? क्या आपके पास उसकी प्रति है? क्या यह भाजपा कार्यालय में बनी है? भाजपा भयभीत है। वे मानसिक रूप से असंतुलित हो चुके हैं। एक तरफ वे कह रहे हैं कि सी.ए.जी. रिपोर्ट पेश नहीं हुई है, लेकिन दूसरी तरफ, वे कह रहे हैं कि

रिपोर्ट जारी हो गई है। वे आखिर कहना क्या चाहते हैं?” इस हमले में कांग्रेस भी शामिल हो गई है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने सी.ए.जी. रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किये जाने में हुये विलम्ब की आलोचना की तथा आरोप

छात्र को फॉरेन मैडिकल ग्रेजुएट...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) के वकील भी याचिकाकर्ता के तथ्य को गलत साबित करने में असफल रहे हैं। याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने नीट-2019 में शामिल होकर 230642 रैंक पाई थी। इसके बाद उसने किर्गिस्तान से एमबीबीएस पाठ्यक्रम पूरा किया था। याचिकाकर्ता ने देश में प्रैक्टिस के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की ओर से आयोजित फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा में आवेदन किया। इस दौरान बोर्ड ने नीट का अंक तालिका नहीं होने की आपत्ति लगाकर प्रवेश पत्र जारी नहीं

लगाया कि यह बात संकेत देती है कि रिपोर्ट को दबाने को लेकर भाजपा और आप के बीच साटगोट है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली की आबकारी नीति को “स्वयं घोषणा” बताया तथा केजरीवाल सरकार पर सरकारी पैसे को बहा देने का आरोप लगाया।

बिल्डर पर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) विपक्षी बिल्डर को फ्लैट का कब्जा सितंबर, 2021 तक दे देना था, लेकिन तय समयवाधि में फ्लैट का कब्जा नहीं दिया गया। इसके बावजूद भी परिवादी हर महीने लोन को किस्त वसूली होती रही। जब उसने लोन किस्त देने से मना किया तो फ्राइन्स कंपनी ने उसकी सिबिल खराब कर दी। इसे उसने जिला उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए उसकी जमा राशि ब्याज सहित दिलवाई जाने का आग्रह किया। जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया है।

दिल्ली...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) ने मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दी हैं। ये प्रतिक्रियाएं उनकी विविध जरूरतों और प्राथमिकताओं को दर्शाती हैं। जहाँ बहुत सी महिलाओं को ये योजनाएं राहत के रूप में तथा स्वागत योग्य लगी हैं, वहीं अन्य महिलाओं ने इनके जारी रहने तथा दीर्घकालीन प्रभाव पर प्रश्न खड़े किये हैं।

भाजपा ने दिल्ली में 29 टिकट और दिये

नयी दिल्ली, 11 जनवरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा की दूसरी लिस्ट में कपिल मिश्रा का नाम शामिल है उनको करावल नगर से टिकट दिया गया है, राज करण खत्री को नरेला से और सूर्य

- राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के घर कोर कमेटी तथा मुख्यालय में केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई।

प्रकाश खत्री कोतिमारपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। गजेन्द्र दयाल को मुंडका से तो बजरंग शुक्ला को किराड़ी सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। करम सिंह कर्मा को सुल्तानपुर माजरा से, करनैल सिंह शर्कर बस्ती सीट से, तिलक राम गुप्ता त्रिगार सीट से, मनोज कुमार जिंदल सदर बाजार से और सतीश जैन को चांदनी चौक से टिकट दिया गया है। भाजपा की इस दूसरी लिस्ट में पांच महिला उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं। शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर भाजपा कोर कमेटी और भाजपा मुख्यालय में केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, इसमें प्रत्याशियों के नाम तय किए गए थे।

लवली कंडारा एनकाउंटर मामले में सी.बी.आई. ने जाँच शुरू की

उदयपुर/जोधपुर, 11 जनवरी (कांस)। सीबीआई दिल्ली ब्रांच ने जोधपुर के रातानाड़ा थाना क्षेत्र में नवीन उर्फ लवली कंडारा एनकाउंटर मामले में, उदयपुर सायबर सैल में तैनात तत्कालीन इंस्पेक्टर लीलाराम सहित, चार कांस्टेबलों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

प्रकरण के अनुसार, 13 अक्टूबर 2021 को जोधपुर की बनाइ रोड पर बदमाश नवीन उर्फ लवली कंडारा और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके दौरान गोली लगने से लवली कंडारा की मौत हो गई और उसके दो साथी फरार हो गए। कंडारा के साथियों ने एनकाउंटर से इंकार करते हुए उस समय अलग कहानी बताई थी। लवली के परिवारों ने रातानाड़ा थाने के एसएचओ लीलाराम व टीम पर लवली कंडारा को गोली मारकर उसकी हत्या करने एवं साक्ष्य मिटाकर एनकाउंटर का रूप देने का आरोप लगाया था। घटना के बाद पांच दिन बाद लवली का अंतिम संस्कार हुआ था। परिवारों ने तत्कालीन गहलौरी सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश करते हुए, रातानाड़ा एसएचओ लीलाराम, जो वर्तमान में उदयपुर सायबर सैल में तैनात हैं, के साथ कांस्टेबल जितेंद्रसिंह,

- उदयपुर के इंस्पेक्टर सहित चार कांस्टेबलों के खिलाफ मामल दर्ज किया।
- वर्ष 2021 में जोधपुर में बदमाश नवीन उर्फ लवली कंडारा और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें लवली मारा गया था।

किशनसिंह, विश्वास व अंकित के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था। अब सीबीआई ने रातानाड़ा थाने में दर्ज प्रकरण के आधार पर मामला दर्ज कर सीबीआई डीएसपी मोहिंदरराम को जांच सीपी है।

ज्ञातव्य है कि इस मामले में 13 अक्टूबर 2021 को एनकाउंटर के बाद लवली कंडारा के साथी द्वारा वीडियो वायरल करने के बाद, हत्या के आरोप लगाए गए थे। वीडियो को देखने के बाद समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल भी इस धरने में शामिल हुए थे। पांच दिन तक परिवारों ने लवली का शव नहीं उठाया था। फिर सरकार ने एडीजी रविप्रकाश मेहरड़ा को भेजकर वार्ता करवाई थी तथा 17 अक्टूबर को एनकाउंटर टीम के लीलाराम सहित पांच पुलिसकर्मियों को निर्वासित करने के बाद परिवारों के लवली का अंतिम संस्कार किया था।

युवा दिवस...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) विभाग, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग (माध्यमिक) तथा शिक्षा विभाग (प्राथमिक) में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों दी जाएंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों का शिलान्यास तथा 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। इनमें ऊर्जा, सार्वजनिक निर्माण, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, पीएचईडी, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, पंचायतराज तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों के कार्य शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी नौकरियों व 6 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार सहित कुल 10 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है।

‘भाजपा सांसद, मंत्री और पूर्व सांसद भारी चुनावी घोटाला कर रहे हैं’

आप नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि ये नेता अपने सरकारी बंगले के पते पर वोटर्स के नाम रजिस्टर करवा रहे हैं

नयी दिल्ली, 11 जनवरी। आम आदमी पार्टी (आप) ने आरोप लगाया कि केन्द्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों व पूर्व सांसदों समेत, अन्य नेता फर्जी पते पर बड़े पैमाने पर फर्जी वोट बनवाकर ‘चुनावी घोटाला’ कर रहे हैं। आप के वरिष्ठ नेता एवं सांसद संजय सिंह ने शनिवार को कहा कि केन्द्रीय मंत्री और सांसद चुनाव आयोग की आंख में धूल झाँक रहे हैं और उसकी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर चुनावी घोटाला कर रहे हैं। नयी दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा पूर्व सांसद हैं। इसके बावजूद, प्रवेश वर्मा मई 2024 से लेकर आज तक पिछले आठ महीने से सांसद का बंगला कब्जा करके बैठे हुए हैं। प्रवेश वर्मा ने अपने सरकारी बंगले के पते पर 33 वोट बनवाने की

- उन्होंने राजस्थान के भाजपा सांसद सी पी जोशी पर 28 वोट रजिस्टर करने का आरोप लगाया।
- संजय सिंह ने पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा, केन्द्रीय मंत्री पंकज चौधरी, कमलेश पासवान, सांसद जय प्रकाश आदि पर भी फर्जी वोट रजिस्टर कराने का आरोप लगाया।

एलोकेशन दी है। सिंह ने केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने सरकारी बंगले के पते पर 26 वोट, केन्द्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने अपने पते पर 26 वोट बनवाने के लिए आवेदन किया है। साथ ही, एक सांसद का पता मुखर्जी स्मृति न्यास है। इस पते पर 31 वोट बनवाने की अर्जी दी गई है। तेरह तीन मूर्ती लेन में उत्तर प्रदेश के हरदोई के रहने वाले भाजपा के सांसद जय प्रकाश के पते पर 25 वोट बनवाने के लिए

आवेदन किया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान से भाजपा के सांसद सीपी जोशी 14 विंडसर प्लेस में रहते हैं। इस पते पर इन्होंने 28 वोट बनवाने के लिए आवेदन किया है। इसी प्रकार, 24 मीना बाग के पते पर रहे सांसद ने 23 वोट बनवाने के लिए आवेदन किया है। छह महानंद रोड पर रहे सांसद दीपें है। 22 वोट, 513 नवगंज हाउस में एक ऑफिस है और यहाँ पर 23 वोट बनवाने के आवेदन दिए गए हैं। सिंह ने बताया कि 87 बेसमेंट

जोरबाग लोधी रोड के पते पर 20 वोट बनवाने के लिए आवेदन किया, जबकि बेसमेंट में रहने का पता नहीं दे सकते। एडीएमसी का फ्लैट पालिका कुंज में है। इस दो बेडरूम के फ्लैट में 19 वोट बनवाने के लिए आवेदन किया गया है। आप नेता ने कहा कि फर्जी वोट बनवाने वालों में मोदी सरकार के केन्द्रीय मंत्री, सांसद, पूर्व सांसद से लेकर ऐसे पते पर वोट बनवाए गए हैं, जिनका कोई पता नहीं है और न उन वोटर्स के बारे में कोई जानकारी है। हम भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं कि आप अपनी पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं और ऐसे फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीतना चाहते हैं। आप देश की राजधानी दिल्ली के अंदर चुनावी धोखाधड़ी कर रहे हैं। क्या यही आपका चुनाव लड़ने का तरीका है?

सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु राज्यपाल को हटाने की याचिका

तमिलनाडु, 11 जनवरी। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्यपाल अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से पूरा नहीं कर रहे हैं। आरोप है कि उनका कार्य राज्य की संवैधानिक प्रणाली के खिलाफ जा रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्यपाल के कामकाज के तरीके से राज्य सरकार और शासन के बीच असहमति और तनाव पैदा हो रहा है। याचिका में राज्यपाल के कुछ फैसलों और उनके काम करने का ढंग पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि राज्यपाल ने राज्य सरकार के साथ कई मुद्दों पर बिना विचार किए हुए हस्तक्षेप किया है, जिससे राज्य की राजनीति में अनावश्यक विवाद बढ़े हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्यपाल को अपनी संवैधानिक भूमिका

- याचिका में आरोप है कि राज्यपाल आर.एन. रवि का कार्य राज्य की संवैधानिक प्रणाली के खिलाफ है।

निभाने के लिए और अधिक संतुलित और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तमिलनाडु में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच पहले भी कई बार मतभेद सामने आ चुके हैं। इन मतभेदों के कारण राज्य की राजनीति में खलबली मची रहती है। राज्य सरकार और विपक्ष दोनों ही राज्यपाल के फैसलों को लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं। ऐसे में यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करना, राज्यपाल के खिलाफ असंतोष का एक और बड़ा कदम माना जा रहा है।

कैलिफोर्निया में आग, लॉस एंजलिस में भारी तबाही

लॉस एंजलिस में 12,000 से ज्यादा इमारतें जल कर राख हो गई हैं, 11 लोगों की जानें गई हैं

- गत मंगलवार को जंगल में आग लगी थी, तेज हवाओं के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।

इस अग्निकांड से अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन करना भी मुश्किल हो रहा है। माना जा रहा है कि यह अमेरिका के इतिहास का सबसे भीषण अग्निकांड है। अमेरिका को किसी भी अग्निकांड में इतना नुकसान आज तक नहीं हुआ। नुकसान का वित्तीय असर अभी स्पष्ट नहीं है। मौसम का डेटा उपलब्ध कराने वाली निजी कंपनी ने अनुमान लगाया है

लॉस एंजलिस, 11 जनवरी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग का तांडव जारी है। लॉस एंजलिस के जंगल में आग की तबाही का मंजर पूरी दुनिया देख रही है। ऐसा लग रहा कि जैसा लॉस एंजलिस पूरी तरह खाक हो चुका है। लॉस एंजलिस में अब तक 12 हजार से अधिक घर-इमारतें खाक हो चुकी हैं। और अब तक 11 लोग अपनी जान गंव चुके हैं। बीते मंगलवार से आग की तबाही शुरू हुई। अब तक इस पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। मंगलवार को जंगल में आग लगी। पर सांता एना हवाओं की वजह से और भी विकराल रूप धारण कर लिया। गुफुवार को आग पर कुछ हद तक काबू पाया गया। मगर मौसम विभाग का कहना है कि वीकेंड में एक बार फिर आग तेज हो सकती है।

बिल्डर पर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) विपक्षी बिल्डर को फ्लैट का कब्जा सितंबर, 2021 तक दे देना था, लेकिन तय समयवाधि में फ्लैट का कब्जा नहीं दिया गया। इसके बावजूद भी परिवादी हर महीने लोन को किस्त वसूली होती रही। जब उसने लोन किस्त देने से मना किया तो फ्राइन्स कंपनी ने उसकी सिबिल खराब कर दी। इसे उसने जिला उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए उसकी जमा राशि ब्याज सहित दिलवाई जाने का आग्रह किया। जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया है।

कि नुकसान करीब 150 बिलियन डॉलर तक हो सकता है। यह नुकसान 150 बिलियन डॉलर है। हालांकि, सरकारी अधिकारियों ने अभी तक नुकसान का कोई अनुमान नहीं दिया है।

‘तृतीय पक्ष का अधिकार...’

(प्रथम पृष्ठ का शेष) समक्ष दावा किया था। जिसे एसडीओ ने साल 2008 में खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता की अपील पर राजस्व अपील अधिकारी (आर ए ए) ने एसडीओ के आदेश के निरस्त कर याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला दिया। वहीं बाद में मालपुरा तहसीलदार ने आर ए के आदेश के खिलाफ राजस्व मंडल में अपील दायर की। जिस पर सुनवाई

जानकारी के अनुसार कुल 12 हजार से अधिक घर-इमारत तबाह हो गई हैं। प्रशांत पॉलिसेड्स के पहाड़ी तटीय इलाके में 5300 से अधिक इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई हैं।

करते हुए मंडल ने आरए के आदेश को निरस्त कर एसडीओ के आदेश को सही माना। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उसके पूर्वजों के नाम दर्ज जमीन को गलत तरीके से राजस्व रिपोर्ट में चढ़ाया गया है, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपिठ ने आदेश दिया है कि भूमि पर किसी तृतीय पक्ष के अधिकार सृजित नहीं किए जाए।

प्रधानमंत्री 13 को सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन करेंगे

बारह किलोमीटर लम्बी 2700 करोड़ की लागत से बनी सुरंग से लेह का रास्ता सुगम होगा

नई दिल्ली, 11 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को जम्मू-कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक, 12 किलोमीटर लंबी इस सुरंग सहित, पूरे प्रोजेक्ट पर 2,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आई है। इसमें सोनमर्ग मुख्य सुरंग, एक एग्जट सुरंग और लिंक रोड शामिल है। समुद्र तल से 8,650 फुट की ऊंचाई पर स्थित यह सुरंग लेह जाने के लिए श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच सभी मौसम में यातायात को सुगम बनाएगी। पीएम मोदी ने ‘एक्स’ पर किए गए

- जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री की वहा की यह पहली यात्रा है। उनकी सुरक्षा के लिये कश्मीर घाटी में व्यापक इंतजाम किये गये हैं।

एक पोस्ट में अपने कश्मीर दौरे की जानकारी दी है। जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के एक कमेंट पर रिएक्ट करते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया। इससे पहले, उमर अब्दुल्ला ने उनकी यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए वहां का दौरा किया और कुछ तस्वीरों और वीडियो साझा किए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जेड-मोड सुरंग के उद्घाटन से सोनमर्ग पूरे साल पर्यटकों के लिए खुला रहेगा।

सोनमर्ग अब एक बेहतरीन स्की रिसॉर्ट के रूप में विकसित होगा। स्थानीय लोगों को सर्दियों में बाहर नहीं जाना पड़ेगा और श्रीनगर से कारगिल/लेह की यात्रा का समय भी कम हो जाएगा। पीएम मोदी ने अब्दुल्ला के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि मैं सुरंग के उद्घाटन के लिए जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग की अपनी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। आपने पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए इसके

लाभों की सही बात कही है। साथ ही, हवाई तस्वीरों और वीडियो भी बहुत पसंद आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 13 जनवरी को प्रस्तावित यात्रा से पहले कश्मीर घाटी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं। एसपीजी, जम्मू-कश्मीर पुलिस और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएफएफ) के साथ समन्वय करके उद्घाटन समारोह स्थल सहित, पूरी सुरक्षा-व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं। मोदी के सुचारु दौरे को सुनिश्चित करने के लिये सुरक्षा-कर्मों 24 घंटे बाज की तरह हर जगह नजर जमाये हुये हैं।